91, 8423 families have been assisted in Arunachal Pradesh under I.R.D.P.

(b) For the year 1991-92 a target of assisting 15022 families was fixed for Arunachal Pradesh and 10888 families were assisted in the State.

(c) In Arunachal Pradesh due to inadeuqate banking and infrastructure facilities capital investments upto Rs. 2000 have been delinked from credit in order to have increased coverage of families. During 1992-93, seven DRDAs have been released full central share of funds in relaxation of the eligibility criterion. This is also expected to result in higher achievement under IRDP in the State.

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3773. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के भारत सरकार के दो प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित समूह के गरीब परिवारों को सहायता दी जाती है जिनमें वे छोटे तथा सीमांत किसान, कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं जिनकी आय गरीबी की रेखा से नीचे है। सरकार द्वारा सबसिडी और बैंकों की मार्फत आवधिक ऋण के रूप में आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि पात्र परिवारों की गरीबी की रेखा पार करने में मदद की जा सके। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 180 लाख परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाना है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के प्रत्यक्ष और निरंतर लाभ तथा ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्पादक स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना भी है ताकि ग्रामीण गरीबों की गरीबी की रेखा पार करने में मदद की जा सके। आठवीं योजना के दौरान उद्देश्य पूरक रोजगार के रूप में प्रति वर्ष कम से कम 1000 मिलियन श्रमदिनों का सृजन करना होगा।

Change in Jawahar Rojgar Yojana

3774. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government of Uttar Pradesh has demanded changes in Jawahar Rozgar Yojana Scheme and if so, what are the changes asked for; and

(b) whether this centraly sponsored scheme is likely to be transferred to the State Governments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir. Broadly, the following changes were suggested by the Government of Uttar Pradesh in the implementation of Jawahar Rozgar Yojana (JRY):—

(i) the wage and non-wage component under the Yojana be revised from 60:40

(ii) a minimum allocation be fixed for each panchayat in the state; and

(iii) JRY should be flexible so that the dovetailing of resources available under different schemes with the JRY resources is possible.

(b) At present, there is no proposal to transfer JRY to the State Governments.

Committee of Members of Parliament reviewing poverty alleviation programme

3775. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a Committee of Members of Parliament and State Legislators to